क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 19 | अक्तूबर 1-15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-8

नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के नतीजों पर

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी–20) के नेताओं के नई दिल्ली के शिखर सम्मेलन को हिन्दोस्तानी मीडिया और पश्चिमी साम्राज्यवादी मीडिया में एक बड़ी सफलता के रूप में सराहा जा रहा है।

इस शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां – संयुक्त घोषणापत्र का सर्वसम्मति से अपनाया जाना और अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करना – मानी जा रही हैं। इसके अलावा, जी–20 के भीतर विभिन्न समूहों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहलों की भी घोषणा की गई, जैसे कि हिन्दोस्तान–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा और जैव ईंधन गठबंधन।

संयुक्त घोषणापत्र का सर्वसम्मति से अपनाया जाना

यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर सदस्य देशों के बीच, खुलकर साफ़–साफ़ आ रहे मतभेदों के कारण संयुक्त घोषणापत्र का सर्वसम्मति से अपनाया जाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इंडोनेशिया में हुए 2022 के शिखर सम्मेलन में ऐसे मतभेद स्पष्ट हो गए थे।

हिन्दोस्तानी सरकार के प्रवक्ता सर्वसम्मति दस्तावेज़ को हिन्दोस्तानी कूटनीति द्वारा हासिल की गयी एक बड़ी सफलता के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिन्दोस्तानी सरकार के प्रतिनिधियों ने इस परिणाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है, परन्तु यह समझना आवश्यक है कि यह सर्वसम्मति हासिल नहीं हो सकती थी, अगर अमरीका ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को दोषी ठहराने पर ज़ोर देने के अपने पूर्व के रवैये में कुछ लचीलापन नहीं दर्शाया होता। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए, सर्वसम्मति दस्तावेज़ देशों के बीच के संबंधों को नियंत्रित करने वाले, आमतौर पर स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय असूल को दोहराता है कि किसी भी देश को किसी दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, परन्तु सर्वसम्मति दस्तावेज़ रूस का नाम नहीं लेता है।

अमरीका के अपने पहले के रवैये में कुछ हद तक लचीलापन दर्शाने के फ़ैसले को हाल के वर्षों में जी–20 की घटती विश्वसनीयता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

जी–20 एक ऐसा समूह है जिसे अमरीका की पहल पर 1999 में स्थापित किया गया था। इसमें दुनिया की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसके सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो–तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी–20 द्वारा फ़ैसले आम सहमति से लिये जाते हैं, अर्थात इनमें सभी सदस्यों की सहमति होती है। इसके वार्षिक शिखर सम्मेलनों में जारी घोषणाएं इसके किसी भी सदस्य देश के लिये बाध्यकारी नहीं होती हैं। परन्तु वे अंतरराष्ट्रीय जनमत को आकार देने का काम करती हैं। विशेष रूप से, जी–20 का उद्देश्य लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि दुनिया की प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियां मानवता के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग कर रही हैं।

हाल के वर्षों में जी–20 की विश्वसनीयता कम हो रही है क्योंकि इसके सदस्यों के बीच अंतर्विरोध तीव्र हो रहे हैं, ख़ासकर 2017 में शुरू हुए अमरीका–चीन के बीच व्यापार युद्ध के बाद से। इस समूह की छवि तब और ख़राब हो गई थी, जब ट्रम्प की सरकार के दौरान अमरीका विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों से बाहर निकल गया था। जनवरी 2021 में जब बाइडन ने कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने अपने विदेश संबंधों को पुनर्गठित और मजबूत करके, दुनिया में अमरीका की अगुवा भूमिका को बहाल करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन आर्गेनाईजेशन (एस.सी.ओ.) जैसे समूहों के विकास के मद्देनज़र, अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए जी–20 की विश्वसनीयता को बहाल करना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उन संगठनों में चीन अगुवा भूमिका निभाता है। इसीलिए अमरीका ने रूस पर अपना रवैया कुछ हद तक हल्का करने का फ़ैसला किया और नई दिल्ली के शिखर सम्मेलन में संयुक्त घोषणा के

शेष पृष्ठ 4 पर

पंजाब और हरियाणा के किसान अपने दावे पर दृढ़ता से डटे हैं

पंजाब और हरियाणा के किसान अपने दावों पर ज़ोर देने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं।

पंजाब के उन्नीस किसान संगठनों ने 28 सितंबर से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय रेल रोको विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। वे हाल की बाढ़ से हुए नुक़सान के लिए मुआवज़े, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की क़ानूनी गारंटी और क़र्ज़ माफ़ी की मांग कर रहे हैं।

एक महीने पहले ही इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर दिया गया था। आंदोलनकारी किसानों ने 2021 की लखीमपुर खीरी घटना, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी, उसके मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने की मांग की। किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के सरवन सिंह पंधेर ने कहा, "अगर पंजाब के किसानों के साथ किसी ने अन्याय करने की कोशिश की तो हरियाणा के किसान भी पंजाब के किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। पूरे देश में किसान एकजुट हैं।"

30 सितंबर को हरियाणा के किसान संगठनों ने पंजाब के किसानों के समर्थन में भारतीय रेल के अंबाला–राजपुरा खंड पर 4 घंटे का रेल रोको अभियान आयोजित किया।

किसान शंभू टोल प्लाजा के पास एकत्र हुए और फिर घेल गांव से होते हुए रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ गए। पटियाला की महिला कृषि कार्यकर्तायें भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।

बी.के.यू. (शहीद भगत सिंह) के नेता तेजवीर सिंह ने कहा, "पंजाब में किसानों के समर्थन में किसानों ने क़रीब 4 घंटे तक रेलवे ट्रैक जाम रखा। कृषि आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और मांगें पूरी नहीं होने पर सरकार को इसकी क़ीमत चुकानी पड़ेगी। आक्रोश की भावना पैदा हो रही है और किसान यूनियनें जल्द ही दिल्ली की ओर बढ़ेंगी।

किसान यूनियनों द्वारा तीन दिवसीय "रेल रोको" विरोध प्रदर्शन 30 सितंबर की शाम को अमृतसर जिले के देवीदासपुरा गांव में रेलवे पटरियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ।

किसान यूनियनों ने घोषणा की है कि हम विरोध प्रदर्शन के अगले चरण के तहत 23–24 अक्तूबर को किसान दशहरा का आयोजन करेंगे। इन दोनों दिन सरकारी नीतियों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए केंद्र सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले जलाए जाएंगे।

किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा, "कॉर्पोरेट समर्थक सरकारें किसानों को भीख का कटोरा थमाने की कोशिश कर रही हैं। हमने सरकार को यह दिखाने के लिए इन कटोरों को तोड़ दिया कि हम भिखारी नहीं बनेंगे और अपने अधिकारों को पाने के लिए लड़ेंगे।" किसानों की एम.एस.पी. के लिए क़ानूनी गारंटी की मांग लंबे समय से लंबित थी क्योंकि अधिकांश फ़सलों की क़ीमतें निजी ख़रीदारों द्वारा तय की जाती थीं। उन्होंने कहा कि "सरकार दो दर्जन से अधिक फ़सलों के लिए एम.एस.पी. की घोषणा करती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से राज्य में यह केवल दो फ़सलों – चावल और गेहूं – पर ही उपलब्ध है। यदि एम.एस.पी. के लिए क़ानूनी गारंटी हो, तो हम उन सभी फ़सलों पर एम.एस.पी. प्राप्त करने में सक्षम होंगे जिन पर इसकी घोषणा की गई है"।

शेष पृष्ठ 8 पर

अंदर पढ़ें

- बैंक क़र्ज़ों से ख़तरनाक संकेत 2
- हिन्द–अमरीका रणनीतिक संबंध 3
- क्यूबा के समर्थन में विश्वव्यापी अभियान 3
- पाठकों की प्रतिक्रिया 4
- रेल दुर्घटनाओं पर गोष्ठी 5
- मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का संघर्ष 5
- नौसेना के ठेका मज़दूरों की समस्याएं 6
- टमाटर की फ़सल पर एम.एस.पी. 6
- बंगाल में परिवहन कर्मचारी अपनी मांगों पर एकजुट 6
- जेएनयू में ठेका मज़दूरों ने "सम्मान रैली" निकाली 6
- कनाडा के सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूरों का प्रदर्शन 7
- अमरीका की कार कंपनियों में हड़ताल 7
- हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के मज़दूरों का संघर्ष 7

बैंकों द्वारा दिए जा रहे क़र्ज़ों में वृद्धि :

एक ख़तरनाक प्रवृत्ति

बैंकों द्वारा दिये गये क़र्ज़ों में बढ़ते पैमाने पर वृद्धि और बैंकों की बेहतर मुनाफ़ाकारिता को हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था के लिये अच्छे हालातों के संकेत के रूप में पेश किया जा रहा है। परन्तु हक़ीक़त यह है कि यह क़र्ज़ वृद्धि, उत्पादन के लिए दिए जाने वाले क़र्ज़ों के बजाय, उपभोग के लिए दिए गये क़र्ज़ों में बढ़ोतरी के कारण हो रही है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। यह एक ख़तरनाक प्रवृत्ति है। इसके अलावा, बैंकों की बेहतर मुनाफ़ाकारिता को हासिल करने के लिये बहुत अधिक सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया गया है, उन क़र्ज़ों की माफ़ी के लिये जिनकी भरपाई पूंजीपति नहीं कर रहे हैं। इसके साथ–साथ बैंकों द्वारा उभोक्ताओं की बचत पर कम ब्याज दिया जा रहा है, जबकि उभोक्ताओं द्वारा लिये गये क़र्ज़ों पर अधिक ब्याज वसूला जा रहा है।

सितंबर 2023 में बैंकों का बकाया क़र्ज़ एक साल पहले की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल मुनाफ़ा 2022–23 में 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक था। पांच साल पहले इन्हीं बैंकों को 85,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। सरकार का दावा है कि अर्थव्यवस्था के लिये ये बहुत अच्छे संकेत हैं, जो दिखाते हैं कि आने वाले वर्षों में हिन्दोस्तान का वित्तीय क्षेत्र तेज़ी से आर्थिक विकास में मदद करने की स्थिति में होगा।

किसे अधिक क़र्ज़ मिल रहा है, इसका विस्तृत विश्लेषण एक काफ़ी अलग तस्वीर दिखाता है। हिन्दोस्तानी बैंक, औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार के बजाय, व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं के लिए अधिक क़र्ज़ दे रहे हैं।

उपभोक्ता–क़र्ज़ की तेज़ी से वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) के मासिक बुलेटिन में खुदरा क़र्ज़ (व्यक्तियों को दिए गए क़र्ज़) की हालिया समीक्षा में बताया गया है कि, "कोविड के बाद की अवधि में बैंकों के द्वारा दिये गये कुल क़र्ज़ में वृद्धि का बड़ा हिस्सा खुदरा क़र्ज़ में हुई वृद्धि की वजह से है।"

जबकि बैंकों द्वारा उद्योगों के लिए दिए जाने वाले क़र्ज़ में गिरावट आई है, तो व्यक्तिगत ग्राहकों के खुदरा क़र्ज़ (आवास–क़र्ज़ या होम लोन, वाहनों और उपभोग की टिकाऊ वस्तुओं के लिए क़र्ज़ तथा क्रेडिट कार्ड के क़र्ज़) में वृद्धि हुई है। आर.बी.आई. द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2014 में उद्योग, व्यापार और सेवाओं के लिए दिया जाने वाला क़र्ज़, बैंकों के कुल क़र्ज़ का 70 प्रतिशत हुआ करता था, जो मार्च 2023 में घटकर 50 प्रतिशत से भी कम हो गया है। इसी अवधि के दौरान, कुल क़र्ज़ में खुदरा–क़र्ज़ का हिस्सा, 18 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया है।

इस साल, मार्च में बैंकों का बकाया खुदरा क़र्ज़ 41 लाख करोड़ रुपये था, जो पांच साल पहले की तुलना में दोगुना हो गया है। इससे निर्माण–सामग्री, टेलीविज़न और अन्य टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं सहित विभिन्न वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने में मदद मिली है।

हिन्दोस्तान में खुदरे–क़र्ज़ को बैंक एक सुरक्षित निवेश मानते हैं। मार्च 2023 तक, केवल 1.4 प्रतिशत खुदरे क़र्ज़ों को न चुकाये जाने वाले क़र्ज़ (डूबंत क़र्ज़) या गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

होम लोन बैंकों द्वारा दिए जाने वाले खुदरा क़र्ज़ का एक बड़ा हिस्सा हैं। हमारे देश में अधिकांश व्यक्तिगत क़र्ज़ लेने वालों के लिए, होम लोन, उनका सबसे बड़ा निवेश होता है। भले ही आर्थिक हालात ख़राब हो जाएं और लोगों की नौकरियां चली जाएं, वे अपने आवास क़र्ज़ की किश्तों को चुकाने पर डिफॉल्ट करने के बजाय, व्यक्तिगत ख़र्च में तेज़ी से कटौती करते हैं। यह बड़े पूंजीपतियों द्वारा लिए गए कर्ज़ों के बिल्कुल विपरीत है, जो "मुश्किल बाज़ार स्थितियों" का बहाना बनाकर अकसर बैंकों को अपने क़र्ज़े की किश्त का भुगतान करना बंद कर देते हैं।

बैंक भी अधिक उपभोक्ता–क़र्ज़ देने के इच्छुक हैं क्योंकि वे अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक हैं। ऐसे क़र्ज़ों पर अधिक ब्याज की गुंजाइश भी होती है। उदाहरण के लिए, अधिकांश बैंकों द्वारा, होम लोन पर ली जाने वाली वार्षिक ब्याज की दर, वर्तमान में 8.5 से 11 प्रतिशत है, जबकि बचत बैंक में जमा राशि पर ब्याज की दर केवल 2.75 से 3.5 प्रतिशत तक है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए क़र्ज़ पर ब्याज की दरें और भी अधिक हैं। सबसे अधिक लाभदायक क्रेडिट कार्ड के क़र्ज़ हैं, जहां बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज प्रति माह 2.5 से 3.5 प्रतिशत तक हो सकता है, यानी जो प्रति वर्ष 30 प्रतिशत से भी अधिक होता है! पिछले एक साल में बकाया क्रेडिट कार्ड क़र्ज़, लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर, 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

कई विकसित पूंजीवादी देशों का अनुभव बताता है कि उपभोक्ता क़र्ज़ की तीव्र वृद्धि एक ख़तरनाक प्रवृत्ति है। यह उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को बढ़ावा देने का काम करती है, जिससे ऐसे सामान बेचने वाले पूंजीपतियों का मुनाफ़ा बढ़ता है। लेकिन ये लोगों को अपनी आमदनी से कहीं अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करके, उपभोक्ता क़र्ज़ और इसके साथ–साथ लोगों के दिवालिया होने का ख़तरा बढ़ा देता है।

अमरीका में 2008 का वित्तीय संकट, आवास के लिए बैंकों द्वारा अत्यधिक और बढ़ा–चढ़ाकर दिए गए क़र्ज़ का नतीजा था। इस संकट के कारण, कई बैंक दिवालिया हो गए, क्योंकि लोग बैंकों को अपना क़र्ज़ नहीं चुका सके। जब बैंकों ने उन घरों पर क़ब्ज़ा कर लिया, जिनके लिए क़र्ज़ दिया गया था, तो लाखों लोग बेघर हो गए।

अमरीकी लोगों को एक भयानक व्यक्तिगत क़र्ज़ के चक्र में धकेल दिया गया था जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाए। ब्याज के भुगतान और मूल क़र्ज़ की अदायगी ने उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनसे छीन लिया। परिणामस्वरूप, लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उधार लेने को मजबूर होना पड़ा।

बैंकों द्वारा खुदरा क़र्ज़ को आगे बढ़ाने की रणनीति के कारण, हिन्दोस्तान में ख़तरे के संकेत की ख़बरें पहले से ही आ रही हैं। एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दशक में उपभोग में व्यय की वृद्धि, घरेलू आमदनी से अधिक रही है। इसका एकमात्र अपवाद 2020–21 का वर्ष है, जब लॉकडाउन ने उपभोग को कम कर दिया था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों की आमदनी उस दर पर नहीं बढ़ी है जिस दर पर उपभोग की वस्तुओं की ख़रीद बढ़ी है और इसलिए, लोगों को या तो बचत से या क़र्ज़ लेकर ख़र्च करना पड़ा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि घरेलू बचत में काफ़ी कमी आई है और साथ ही उन पर क़र्ज़ का बोझ बढ़ गया है।

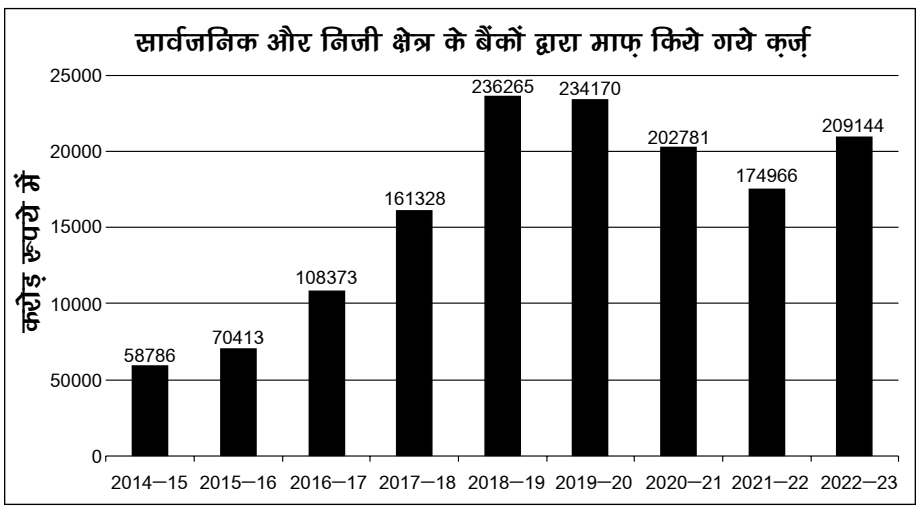

2009–10 और 2010–11 में घरेलू क़र्ज़, घरेलू बचत से थोड़ा ही अधिक था, जिसका मतलब है कि एक वर्ष की बचत सभी घरेलू क़र्ज़ों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त थी। 2021–22 में घरेलू क़र्ज़ को चुकाने के लिए 1.8 वर्ष की बचत की आवश्यकता थी।

जून 2023 में, भारतीय रिज़र्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (एफ.एस.आर.) ने बताया कि मार्च 2021 और मार्च 2023 के बीच खुदरा बैंक क़र्ज़ 24.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़े, जो कि सभी क़र्ज़ों की वृद्धि की दर से लगभग दोगुना था।

हिन्दोस्तानी पूंजीपति, देश की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में निवेश नहीं कर रहे हैं। पूंजीपतियों द्वारा लिए जाने वाले औद्योगिक क़र्ज़ की मांग के घटने के कारण, बैंकों के क़र्ज़ के पैटर्न में बदलाव ज़रूरी हो गया है।

बैंक मुनाफ़ाकारी में सुधार – किसके हित की बली चढ़ाकर?

बैंकों की अच्छी वित्तीय सेहत और अधिक क़र्ज़ देने की उनकी क्षमता, बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजीवादी कंपनियों के क़र्ज़ों को माफ़ करने का परिणाम है, जिसके लिए केंद्र सरकार के बजट से धन दिया गया है। 2022–23 तक, पिछले नौ वर्षों के दौरान, बैंकों द्वारा कुल 14.56 लाख करोड़ रुपये के क़र्ज़ माफ़ किये गये हैं। राइट–ऑफ (पूंजीपतियों के क़र्ज़ माफ़ करने की गतिविधि) की गति पिछले पांच वर्षों में और भी तेज़ हो गई, जब हर साल लगभग दो लाख करोड़ रुपये के क़र्ज़े राइट–ऑफ किए गए।

इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एन.पी.ए., 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के शिखर से गिरकर, 2022–23 तक 4.28 लाख करोड़ रुपये पर आ गया। भारतीय रिज़र्व बैंक की एफ.एस.आर. के अनुसार, कुल क़र्ज़ के प्रतिशत के रूप में सकल एन.पी.ए. मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर मार्च 2023 में 10 साल के सबसे निचले स्तर पर, यानी 3.9 प्रतिशत पर आ गया है।

क़र्ज़ माफ़ी के सबसे बड़े लाभार्थी इजारेदार पूंजीपति हैं जो बैंकों से सबसे बड़ी मात्रा में क़र्ज़ प्राप्त करते हैं। इजारेदार घरानों में से, दस सबसे बड़े क़र्ज़दारों को, 31 मार्च, 2015 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, कुल मिलाकर 7,32,780 करोड़ रुपये का क़र्ज़ दिया गया था। इस सूची में रिलायंस, वेदांत, एस्सार, अदानी और जेपी समूह की कंपनियां शीर्ष पर थीं। इजारेदार घराने, किसी भी प्रकार के निवेश या सट्टेबाज़ी के लिए ऐसे क़र्ज़ स्वीकृत कराने में माहिर हैं। जब तक वे अधिकतम मुनाफ़ा कमाते हैं, वे बैंक क़र्ज़ चुकाते हैं। जब उन्हें उनका अपेक्षित मुनाफ़ा नहीं मिलता, तो वे बैंकों को भुगतान करना बंद कर देते हैं।

इतनी बड़ी मात्रा में पूंजीपतियों के क़र्ज़ों के माफ़ किये जाने के कारण सार्वजनिक बैंकों को होने वाले नुक़सान की भरपाई के लिए, केंद्र सरकार ने 2014–15 और 2020–21 के बीच सार्वजनिक बैंकों में 3.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया। पूंजी के इस प्रवाह के बिना, सार्वजनिक बैंक आगे क़र्ज़ देने में सक्षम नहीं होते – चाहे खुदरा हो या औद्योगिक। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान 'अच्छी सेहत' इजारेदार पूंजीपतियों के क़र्ज़ों को बड़ी मात्रा में माफ़ करके हासिल की गई है।

इसे बहुत भारी सार्वजनिक खर्चे के द्वारा हासिल किया गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि सार्वजनिक धन का उपयोग क़र्ज़ न चुकाने वाले पूंजीपतियों के हित में किया गया है।

निष्कर्ष

यह हक़ीक़त कि बैंक क़र्ज़ में तेज़ी से वृद्धि मुख्य रूप से उपभोक्ता क़र्ज़ से प्रेरित है, यह अर्थव्यवस्था के स्वस्थ होने का संकेत नहीं है बल्कि एक ख़तरनाक प्रवृत्ति का संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि कामकाजी लोग अधिक उधार ले रहे हैं और कम बचत कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बेहतर मुनाफ़ाकारिता पर जश्न मनाने की बात नहीं है, क्योंकि यह पूंजीपतियों द्वारा दिए गए क़र्ज़ों को माफ़ करने के लिए भारी मात्रा में सार्वजनिक धन ख़र्च करके हासिल किया गया है। इस हक़ीक़त पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक कामकाजी लोगों को लूटकर मुनाफ़ा कमा रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ता क़र्ज़ पर ब्याज की दर, जमा धन पर दिए जाने वाले ब्याज की दर की तुलना में बहुत अधिक हैं।

http://hindi.cgpi.org/24049

हिन्दोस्तान–अमरीका के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के क़दम

8 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जी–20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एक बैठक के बाद, एक संयुक्त बयान जारी किया। दोनों देशों के नेताओं ने हिन्दोस्तान–अमरीकी रणनीतिक संबंधों को गहरा और विविधतापूर्ण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बयान में अंतरिक्ष और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तारित सहयोग और बढ़ते रक्षा औद्योगिक सहयोग का आह्वान किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस साल जून में की गयी अमरीका की यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए उठाए गए क़दमों का उल्लेख किया गया।

हिन्दोस्तान में संयुक्त रूप से जनरल इलेक्ट्रिक (जी.ई.) एफ–414 जेट इंजन बनाने के लिए अमरीकी कंपनी जी.ई. एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनौटीकल्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) के बीच बातचीत काफ़ी आगे के चरण में है। अमरीका इन इंजनों के निर्माण की तकनीक हिन्दोस्तान के साथ सांझा करेगा।

अमरीका और हिन्दोस्तान के बीच एक मास्टर शिप रिपेयर समझौता संपन्न हुआ है। इस पर अगस्त 2023 में अमरीकी नौसेना और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह इस तरह का दूसरा समझौता है। हिन्दोस्तानी सरकार दुनिया के दूर–दराज़ के इलाकों में तैनात किये जाने वाले अमरीकी नौसेना के अग्रगामी जहाजों और विमानों के रखरखाव और मरम्मत के लिए हिन्दोस्तान को एक केंद्र के रूप में विकसित करने पर सहमत हो गई है। अमरीकी जहाजों और विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए उन्नत सुविधाएं बनाने में अमरीका हिन्दोस्तान की सहायता करेगा।

एक नयी टीम हिन्दोस्तान–अमरीका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम (इंडस – एक्स) की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य रक्षा संबंधी अनुसंधान पर दोनों देशों के वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों के बीच घनिष्ठ और सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करना है। इंडस–एक्स पहले ही अमरीकी विश्वविद्यालयों और हिन्दोस्तान में अनेक आई.आई.टी. के साथ कई स्टार्टअप सांझेदारियां कर चुका है।

रक्षा मंत्रालय के इन्नोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस (रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार) और अमरीकी रक्षा विभाग के डिफेंस इन्नोवेशन यूनिट (रक्षा नवाचार इकाई) ने दो संयुक्त कार्यक्रम शुरू करने के निर्णय की घोषणा की है। वे रक्षा प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का समाधान विकसित करने के लिए स्टार्टअपों को आमंत्रित करेंगे।

अमरीकी और हिन्दोस्तानी कंपनियां 5–जी और 6–जी तकनीक विकसित करने पर मिलकर काम करेंगी। अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टरों के विकास सहित, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में हिन्दोस्तान–अमरीका के सहयोग का विस्तार करने के निर्णय की घोषणा की गई।

हिन्दोस्तान अमरीका से 31 जनरल एटॉमिक्स एम.क्यू.–9बी (16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन) दूर से संचालित विमान और उनसे जुड़े उपकरण ख़रीद रहा है। ये ड्रोन हिन्दोस्तान के सशस्त्र बलों की खुफ़िया, निगरानी और सैनिक परीक्षण की क्षमताओं को बढ़ाएंगे।

इन घटनाक्रमों से हिन्दोस्तान–अमरीकी सैन्य रणनीतिक गठबंधन की सब तरफ़ा मजबूती स्पष्ट हो जाती है।

पिछले 75 वर्षों में, हिन्दोस्तान ने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के निर्माण और रखरखाव के लिए स्वदेशी क्षमता विकसित की है। इसने विभिन्न दूरियों तक मार करने वाली मिसाइलों के साथ–साथ मिसाइल प्रक्षेपण क्षमताओं का भी विकास किया है। इसके पास एक सुविकसित अंतरिक्ष कार्यक्रम और परमाणु हथियार भी हैं। क़दम दर क़दम, अमरीका हिन्दोस्तान के रक्षा क्षेत्र के विभिन्न घटकों – जिसमें सशस्त्र बल, रक्षा उद्योग और उच्च तकनीकी संस्थानों के अनुसंधान विभाग शामिल हैं – को अपने सैन्य औद्योगिक परिसर के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है। हिन्दोस्तान के वैज्ञानिक और इंजीनियर अनुसंधान करेंगे और स्टार्टअप बनाएंगे जो अमरीकी जंग व्यवस्था की सेवा करेंगे। अमरीका इस इलाके में अपने सैन्य अभियानों के लिए अग्रिम अड्डों के रूप में हिन्दोस्तान की सैन्य सुविधाओं का उपयोग करेगा।

वर्तमान समय में अमरीकी साम्राज्यवादी हिंद–प्रशांत महासागर क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में चीन को मुख्य बाधा के रूप में देखते हैं। वे इस क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी रणनीति में हिन्दोस्तान को एक भागीदार के रूप में शामिल करने के इच्छुक हैं। वे चीन के ख़िलाफ़ हिन्दोस्तानी शासक वर्ग को उकसा रहे हैं।

हिन्दोस्तानी शासक वर्ग की अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं हैं। वह चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता में, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका और चीन के बीच की बढ़ती टक्करों का उपयोग करना चाहता है। वह अमरीकी नमूने के अनुसार और अमरीका की सहायता से एक सैन्य औद्योगिक परिसर बनाना चाहता है।

अमरीकी साम्राज्यवादी चाहते हैं कि एशिया के देश आपस में लड़ें और एक–दूसरे को नष्ट कर दें, जिससे इस महाद्वीप पर अमरीका के प्रभुत्व का मार्ग खुल जाए। वे इस उद्देश्य के लिए हिन्दोस्तानी शासक वर्ग की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

2016 में, अमरीका ने हिन्दोस्तान को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में वर्गीकृत किया था और हिन्दोस्तानी सशस्त्र बलों को कुछ उच्च स्तरीय हथियार प्रणालियों की आपूर्ति करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। इन हथियारों को इससे पहले अमरीका केवल अपने नाटो सहयोगियों को ही दिया करता था। हिन्दोस्तान ने अमरीका के साथ चार बुनियादी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं – बेसिक एक्सचेंज एंड कोओपरेशन एग्रीमेंट फॉर जिओस्पाश्यिल इंटेलिजेंस (भू–स्थानिक खुफ़िया जानकारियों के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, बी.ई.सी.ए.), जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिटरी इंफोर्मेशन (सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा का समझौता, जी.एस.ओ.एम.आई.ए.), लोजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (रसद विनिमय समझौता ज्ञापन, एल.ई.एम.ओ.ए.), कम्यूनिकेशंस कम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता, सी.ओ.एम.सी.ए.एस.ए.)। इन समझौतों ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच नजदीकी से काम करने का रास्ता तैयार किया है। अमरीकी सशस्त्र बलों के हिन्द–प्रशांत महासागर कमान ने हिन्दोस्तानी सशस्त्र बलों के साथ सीधे काम करने के लिए, नई दिल्ली में एक केंद्र स्थापित किया है, ताकि वे सरकार को सूचित किये बिना ही सीधे तौर पर सेना के साथ काम कर सकें।

अमरीकी साम्राज्यवादी एशिया और पूरी दुनिया पर क़ब्ज़ा करने के लिए अपनी आपराधिक युद्ध योजनाओं में हिन्दोस्तानी लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह पूरी तरह से हिन्दोस्तान और अन्य देशों के लोगों के हितों के ख़िलाफ़ है।

हमें हिन्दोस्तान और अमरीका के बीच मजबूत हो रहे सैन्य रणनीतिक गठबंधन का डटकर विरोध करना चाहिए। अमरीकी साम्राज्यवाद हिन्दोस्तानी जनता का मित्र न तो कभी रहा है और न ही रहेगा।

http://hindi.cgpi.org/24057

क्यूबा के समर्थन में विश्वव्यापी अभियान

दुनियाभर के कलाकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता, जन आंदोलन, ट्रेड यूनियन और राजनीतिक पार्टियां एक ऐतिहासिक अभियान में साथ आए हैं। उन्होंने मांग की है कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन क्यूबा को आतंकवाद के तथाकथित प्रायोजक राज्य की अपने देश की सूची से हटा दें।

इस अभियान को आयोजित करने वाले संगठन इंटरनेशनल पीपुल्स असेंबली (आईपीए), एएलबीए मोविमिएंटोस, फोरो डी साओ पाउलो, ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ऑफ द अमेरिकाज, जोर्नडा कॉन्टिनेंटल पोर ला डेमोक्रेशिया वाई कॉन्ट्रा एल नियोलिबरलिस्मो, वर्ल्ड मार्च ऑफ विमेन, कॉन्टिनेंटल लैटिन अमरीकन तथा क्यूबा के साथ एकजुटता में कैरेबियन नेटवर्क और ला विया कैम्पेसिना भी हैं। इस अभियान के आयोजकों ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक राज्यों की सूची से हटाने की मांग की करते हुए, अमरीकी राष्ट्रपति के नाम से एक पत्र लिखा है और उस पत्र पर दस लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। योजना यह है कि इस पत्र को 10 दिसंबर, 2023 को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर राष्ट्रपति बाइडन को दिया जाये।

पत्र में कहा गया है कि क्यूबा को इस सूची में शामिल करने से, "क्यूबा के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणालियों का उपयोग करके लेनदेन करने और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ईंधन, भोजन, निर्माण आपूर्ति, स्वच्छता उत्पाद और दवा जैसे आवश्यक सामान प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है।"

जिन जाने–माने व्यक्तियों ने अभियान पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। उनमें शामिल हैं प्रसिद्ध ब्राजीलियाई संगीतकार चिको बुर्के सहित मैक्सिकन मुरैना पार्टी के सीनेटर और महासचिव सिटाल्ली हर्नांडेज; बेल्जियम वर्कर्स पार्टी के अध्यक्षय पीटर मर्टेंस; विद्वान और महिला अधिकार कार्यकर्ता जूडिथ बटलर; पूर्व कोलंबियाई राष्ट्रपति अर्नेस्टो सैम्पर; और बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस शामिल हैं।

यह विदित है कि अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने 11 जनवरी, 2021 को घोषणा की थी कि "राज्य विभाग ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में नामित किया है"। क्यूबा के साथ ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि क्यूबा ने वेनेजुएला की जायज़ तरीक़े से चुनी गई सरकार को गिराने और उस देश के ख़िलाफ़ व्यापार के बहिष्कार को लागू करने के अमरीका के प्रयासों का विरोध किया था। अमरीका ने क्यूबा पर "आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय देने में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की कार्यवाहियों को समर्थन प्रदान करने" का आरोप लगाया है।

आंतकवाद के प्रायोजक के नाम पर अमरीका ने क्यूबा पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें शामिल है, अमरीका से क्यूबा की यात्रा और दोनों देशों के बीच धन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, जिसकी वजह से क्यूबा के कई परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनके रिश्तेदार अमरीका में रहते हैं।

क्यूबा में 1959 में हुई क्रांति की जीत ने अपने देश से अमरीका समर्थित सत्ता को उखाड़ फेंका था। तब से अमरीका ने क्यूबा के साथ समान संबंध स्थापित करने से इनकार किया है। उसने क्यूबा के लोगों की संप्रभुता और अपनी पसंद की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अपनाने के उनके अधिकार का सम्मान करने से इनकार किया है। अमरीकी साम्राज्यवादी राज्य ने क्यूबा के लोगों के ख़िलाफ़ लगातार आर्थिक और सैनिक हमले किए हैं, जिनमें शामिल हैं हस्तक्षेप करना, क्यूबा के नेताओं की हत्या करने के प्रयास, नागरिकों के ख़िलाफ़ आतंकवादी हमले, आर्थिक प्रतिबंध लगाना और व्यवस्थित रूप से आर्थिक तोड़फोड़।

अमरीकी राज्य ने क्यूबा के ख़िलाफ़ अपनी आर्थिक नाकेबंदी और नीतियों के ज़रिए, क्यूबा की अर्थव्यवस्था को भारी नुक़सान पहुंचाया है। अन्य बातों के अलावा, गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को देने से इनकार करने के लिए भी अमरीका ज़िम्मेदार है।

जबकि दूसरी ओर, पूरी दुनिया क्यूबा के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के वीरतापूर्ण प्रयासों की गवाह है। जिन्होंने 2020 में कोविड–19 महामारी सहित प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप और महामारी आदि के संकट का सामना कर रहे, अन्य देशों में जाकर लोगों की सहायता की है।

अमरीका दुनिया का सबसे प्रमुख आतंकवादी देश है। जिन देशों ने अमरीकी साम्राज्यवाद की लाइन के अनुसार चलने से इनकार किया है, उसने उन देशों के ख़िलाफ़ क्रूर हस्तक्षेप के साथ–साथ सशस्त्र हमला और क़ब्ज़ा किया है, उनके बारे में झूठ फैलाया है और उन्हें बदनाम किया है। अमरीकी राज्य ने क्यूबा के अलावा, ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया को "आतंकवाद के प्रायोजक" के रूप में बदनाम किया है। दुनियाभर में हो

शेष पृष्ठ 5 पर

जी20 शिखर सम्मेलन ...

पृष्ठ 1 का शेष

सर्वसम्मति से अपनाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए हिन्दोस्तान के साथ मिलकर काम किया।

अफ्रीकी संघ का प्रवेश

इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को, यूरोपीय संघ के समान, जी–20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फ़ैसला लिया गया।

हिन्दोस्तान की सरकार के प्रवक्ता खुद को दुनिया के कम विकसित देशों, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है के चैंपियन के रूप में स्थापित करने के अपने प्रयासों के तहत, अफ्रीकी संघ के प्रवेश का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं।

दरअसल, अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दिसंबर 2022 में अफ्रीकी संघ के नेताओं के साथ बैठक में प्रस्ताव किया था कि अफ्रीकी संघ को जी–20 का सदस्य बनाया जाए। अफ्रीकी संघ को जी–20 में शामिल करना इस हक़ीक़त को छिपाता है कि जी–20 वास्तव में दुनिया की प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियों का एक समूह है, जिसमें वे शक्तियां भी शामिल हैं जो मुख्य रूप से अफ्रीका की लूट और उस महाद्वीप में व्यापक ग़रीबी की हालतों के बने रहने के लिए ज़िम्मेदार हैं। अफ्रीकी संघ का जी–20 का सदस्य बन जाने से जी–20 का साम्राज्यवादी चरित्र बदलने वाला नहीं है।

संयुक्त घोषणा का मूल तत्व

जहां तक संयुक्त घोषणा के मूल तत्व का सवाल है, यह काफ़ी हद तक समावेशी विकास, सतत विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे खोखले वादों के रूप में है। हालांकि ऐसे वादे दर्शाते हैं कि दुनिया के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के ढांचे के भीतर ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक उत्पादन अधिकतम निजी मुनाफ़े के लिए इजारेदार पूंजीपतियों की लालच से प्रेरित होता है।

खोखले वादों के अलावा, कुछ ऐसे लक्ष्य भी हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति हासिल करने की गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं, जिनका संयुक्त घोषणा में प्रमुख स्थान है। इनमें शामिल हैं (क) बहुपक्षीय विकास बैंकों का सुधार, (ख) हरित ऊर्जा में परिवर्तन, और (ग) डिजिटल परिवर्तन।

बहुपक्षीय विकास बैंकों का सुधार

विश्व बैंक और आई.एम.एफ. दुनिया के ग़रीब देशों और लोगों के बीच अधिक से अधिक अलोकप्रिय हो गए हैं। अब व्यापक तौर पर यह समझा जा रहा है कि ये संस्थान अमरीका के वर्चस्व में हैं तथा ये मुख्य रूप से अमरीका और अन्य उन्नत पूंजीवादी देशों की सेवा में काम करते हैं। उन्होंने इन देशों के इजारेदार पूंजीपतियों के हितों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जबकि कम विकसित देशों को ज्यादा से ज्यादा विदेशी क़र्ज़ पर निर्भरता की ओर धकेल दिया है।

ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और आपातकालीन फंडिंग के लिए ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व आवंटन जैसे वित्त के वैकल्पिक चैनलों के उत्पन्न होने से, इन संस्थानों के भविष्य के बारे में संदेह भी बढ़ गया है।

अमरीका और प्रमुख यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां दुनिया के कम विकसित और अत्यधिक क़र्ज़े में डूबे हुए देशों के लिए बहुपक्षीय क़र्ज़े के मुख्य चैनल के रूप में विश्व बैंक और आई.एम.एफ. की भूमिका को बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। वे साम्राज्यवादी शक्तियां इन संस्थानों की उधार देने की क्षमता को बढ़ाना चाहती हैं, और वैकल्पिक क़र्ज़ देने के चैनलों के विकास को रोकना चाहती हैं। इन संस्थानों में सुधार की सारी चर्चा के पीछे यही असली उद्देश्य है।

हरित ऊर्जा में परिवर्तन

तथाकथित हरित ऊर्जा में परिवर्तन का एजेंडा इस तरह प्रस्तुत किया गया है जैसे कि यह प्राकृतिक पर्यावरण को हुए नुक़सान को पलटने के उद्देश्य से प्रेरित है। लेकिन वास्तव में यह इजारेदार पूंजीवाद की अधिकतम मुनाफ़ों की लालच से प्रेरित है।

जून 2020 में दावोस में वर्ल्ड इकनोमिक फोरम (विश्व आर्थिक मंच) पर, विश्व साम्राज्यवाद के प्रमुख प्रतिनिधियों ने तथाकथित ग्रेट रीसेट (महान पुनर्नियोजन) की अवधारणा को बढ़ावा दिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि कोविड महामारी से पैदा हुआ संकट जीवाश्म ईंधनों (पेट्रोलियम और कोयला) पर निर्भरता से हटकर ऊर्जा के अन्य स्रोतों, जैसे कि पनबिजली, सौर ऊर्जा, पवन व परमाणु ऊर्जा के साथ–साथ एथानोल जैसे जैव ईंधन से बिजली पैदा करने तक, एक बड़ा बदलाव करने का अवसर था। विश्व स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर पैनल की बिक्री में बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है।

पेट्रोलियम और कोयले से हट जाने को पर्यावरण की रक्षा के आधार पर उचित ठहराया जा रहा है। इसका असली मक़सद संकटग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था को नया जीवन देना है। पेट्रोलियम और कोयले के स्थान पर अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग से ऑटोमोबाइल और कई अन्य उद्योगों में उत्पादन के पुराने साधनों के स्थान पर नई उत्पादन क्षमता आएगी। इससे बड़े पैमाने पर नए बाज़ारों का निर्माण होगा और अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी द्वारा अधिकतम मुनाफ़ा प्राप्त करने के नए अवसर पैदा होंगे।

नई दिल्ली में जी–20 शिखर सम्मेलन के परिणामों में से एक था, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायन्स (वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन) का उद्घाटन, जिसमें अमरीका के साथ–साथ, हिन्दोस्तान, ब्राज़ील, इटली, कनाडा, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका संस्थापक सदस्य थे।

डिजिटल परिवर्तन

हाल के वर्षों में मोबाइल फोन का उपयोग करके डिजिटल भुगतान सहित डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हिन्दोस्तान की सरकार ने यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (यू.पी.आई.) की स्थापना करके इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यू.पी.आई. सार्वजनिक संपत्ति है, जिसका पेटीएम, गूगल पे, भीम, आदि जैसे कई ऐप्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हिन्दोस्तान की सरकार यू.पी.आई. के फ़ायदों को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के अन्य देशों तक बढ़ाने के लिए उत्सुक है।

अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग इस एजेंडे में रुचि रखता है क्योंकि (क) यह सभी लोगों की बचत के धन को बैंकिंग व्यवस्था के अन्दर लाता है, और (ख) सभी लोगों के बारे में सूचना (डाटा) तक पूंजीपति वर्ग को पहुंच दिलाता है।

नया आर्थिक गलियारा

बाइडन और मोदी द्वारा सह–आयोजित एक कार्यक्रम में, हिन्दोस्तान–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण के लिए एक समझौते की घोषणा की गई। उस समझौते के ज्ञापन पर संयुक्त राज्य अमरीका, हिन्दोस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य हिन्दोस्तान, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच समुद्री तथा रेल लिंक विकसित करना है। यह प्रस्तावित किया गया है कि रेल लिंक के साथ–साथ इलेक्ट्रिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल भी होंगे। हाइड्रोजन की सप्लाई के लिए एक पाइपलाइन भी होगी। यह अमरीका द्वारा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का मुक़ाबला करने का एक प्रयास है। इस नयी आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए धन जुटाने के साधनों या समय सीमा के बारे में अभी तक विस्तार से कुछ नहीं बताया गया है।

हिन्दोस्तान की भूमिका

हिन्दोस्तान खुद को "ग्लोबल साउथ" (आर्थिक रूप से कम विकसित देशों) के हितों के एक प्रमुख हिमायती के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हिन्दोस्तान की सरकार कम विकसित देशों या हिन्दोस्तान के मेहनतकश लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वह इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व में हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग ने इस वर्ष जी–20 की अध्यक्षता को अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा अवसर माना है। दुनिया के कम विकसित देशों के हितों की वकालत करने की सभी बातों के पीछे, हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों के उन देशों के बाज़ारों में और अधिक घुसपैठ करने तथा वहां के उपलब्ध विभिन्न क़ीमती कच्चे पदार्थों पर क़ब्ज़ा करने के हित छिपे हुए हैं। हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग के साम्राज्यवादी लक्ष्यों के हासिल होने से करोड़ों हिन्दोस्तानी लोगों को अपनी असहनीय हालतों से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, न ही दुनिया के अन्य उत्पीड़ित देशों और लोगों के हितों की पूर्ति होगी।

http://hindi.cgpi.org/24059

मज़दूर एकता लहर

(इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : http://www.hindi.cgpi.org
अंग्रेजी : http://www.cgpi.org
पंजाबी : http://www.punjabi.cgpi.org
मराठी : http://www.marathi.cgpi.org
तामिल : http://www.tamil.cgpi.org
ईमेल : mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

पाठकों की प्रतिक्रिया

बीमा – 'डर' का व्यापार

संपादक महोदय,

मज़दूर एकता लहर के अंक सितंबर 1–15, 2023 में प्रकाशित लेख 'फ़सल बीमा के ज़रिए किसानों की पूंजीवादी लूट' को पढ़ा। यह लेख काफ़ी जानकारी भरा है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा फ़सल बीमा के ज़रिए पूंजीपतियों द्वारा किसानों की लूट की सच्चाई को सामने लाता है।

जब मैं इस लेख को पढ़ रहा था, तब यह ख्याल आया कि आख़िरकार हम बीमा क्यों करवाते हैं। यह एक डर है कि व्यक्ति की असमय मौत के बाद उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा? पैसे के अभाव में बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए धन कौन खर्च करेगा? यदि उसे या उसके परिवार को कोई गंभीर बीमारी हो गई तो इलाज पर होने वाला बड़ा खर्च कौन सहेगा?

इसी तरह से एक किसान को डर है कि प्राकृतिक आपदा या ख़राब बीज के चलते उसकी फ़सल बर्बाद हो गयी तो लागत की भरपायी कौन करेगा? अर्थात मज़दूरों और किसानों को अपने जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा की असुरक्षा महसूस होती है।

दरअसल, हम पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। यह पूंजीवादी व्यवस्था अनिश्चितताओं और असुरक्षाओं से भरी हुई है। यहीं से 'डर' का व्यापार शुरू होता है, इसी डर के कारण यह व्यापार फल–फूल रहा है। हमारे देश में रोज़गार का अधिकार, आवास का अधिकार, भोजन और एक समान शिक्षा प्राप्त करने व स्वास्थ्य लाभ पाने का सर्वव्यापी अधिकार नहीं है। ऐसे में हर नागरिक अनिश्चितता और असुरक्षा में जीता है। वह अनिश्चितता और असुरक्षा से बचने की कोशिश करता है। पूंजीपतियों की बीम कंपनियां 'जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी' जैसे सुनहरे नारे लगाती हैं। यही डर उनके मुनाफ़े का स्रोत बन जाता है। इस डर के बिजनेस का उत्पादकता से कोई संबंध नहीं है।

किसान फ़सल का बीमा इसलिए करवाते हैं, ताकि फ़सल के बर्बाद होने पर नुक़सान की भरपाई हो सके। किसान अपनी फ़सल की बर्बादी पर जब बीमा राशि (के मुआवज़े) का दावा करते हैं, तो उनके दावे को मानने से इनकार कर दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जब किसानों को अपनी फ़सल की बर्बादी का मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए सड़कों पर आने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस तरह के उदाहरण आपको पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि में भर–भरके मिलेंगे।

जबकि सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना से किसान खुशहाल हो रहा है। परन्तु हो उल्टा रहा है कि पूंजीपति खुशहाल हो रहे हैं और उनकी बीमा कंपनियां मालामाल हो रही हैं।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य और उसकी सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वे देश के किसानों की फ़सलों के नुक़सान की भरपाई की गारंटी दे और यह सुनिश्चित करे कि किसानों को उचित मुआवज़ा मिले।

यह सुनिश्चित करने के लिये मज़दूरों और किसानों को इस पूंजीवादी लूट की व्यवस्था को ख़त्म करना होगा। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी होगा जहां आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक फ़ैसले लेने की ताक़त लोगों के पास होगी।

आपका पाठक
हरीश, दिल्ली

रेल चालकों का द्विवार्षिक अधिवेशन :

रेल दुर्घटनाओं पर गोष्ठी

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

27 सितंबर, 2023 को आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) के मुरादाबाद मंडल का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। रेलगाड़ियों के पटरियों से उतर जाने की बढ़ती दुर्घटनाओं और लाल सिग्नल को पास कर जाना (एस.पी.ए.डी.–स्पैड) को केंन्द्र में रखते हुये ए.आई.एल.आर.एस.ए. ने इस अधिवेशन का विषय रखा था – 'सेफ्टी सेमीनार ऑन मिशन शून्य स्पैड एवं द्विवर्षीय मंडल कान्फ्रेस'।

इस अधिवेशन में मुरादाबाद मंडल की सभी लाबियों से आये रेल चालकों सहित, मुरादाबाद की स्थानीय लाबी के रेल चालकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। अलग–अलग लाबियों से आये हुये प्रतिनिधियों से पूरा हाल भरा हुआ था।

अधिवेशन को दो सत्रों में आयोजित किया गया था, पहला सत्र 'सेफ्टी सेमीनार' था। दूसरा सत्र ए.आई.एल.आर.एस.ए. के मुरादाबाद मंडल के द्विवार्षिक अधिवेशन और मंडल कमेटी के गठन पर केन्द्रित था।

अधिवेशन में ए.आई.एल.आर.एस.ए. की केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से महासचिव के.सी. जेम्स को मुख्य अतिथि बतौर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामसरन, पदम गंगवार आदि, को मुख्य वक्ता बतौर आमंत्रित किया गया था। अधिवेशन में आल इंडिया गार्ड्स काउंसिल तथा एन.आर.एम.यू. के प्रतिनिधियों को भी अपने विचार रखने के लिये आमंत्रित किया गया था।

अधिवेशन के पहले सत्र में भारतीय रेल में हो रही दुर्घटनाओं को कैसे बिल्कुल ख़त्म किया जाये और लाल सिग्नल को

पास कर जाने की समस्याओं को समाप्त करने के लिये क्या–क्या क़दम उठाये जायें, इस पर गहन चर्चा की गई।

इस सत्र के लिये रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था, ताकि रेल चालकों के सामने आने वाली समस्याओं को उनके सामने उठाया जा सके तथा अधिकारी भी दुर्घटनाओं के कारणों और समस्याओं के निराकरण पर अपने विचार प्रकट करें और रेल चालकों की समस्याओं के समाधान के लिये अपने विचार दें।

विदित रहे कि रेलवे में हो रही दुर्घटनों में मुख्य रूप से वे घटनायें हैं, जिनमें गाड़ियां पटरियों से उतर जाती हैं या गाड़ियों में टक्कर हो जाती है, इस तरह की घटनाओं में बहुत से लोगों की मौत हो जाती है और अनेकों घायल हो जाते हैं। इसके साथ–साथ भारतीय रेल की करोड़ों की संपत्ति को नुक़सान होता है, जो जनता के पैसे को लगाकर बनाई जाती है। ऐसी दुर्घटनायें हो जाने के बाद भारतीय रेल कई बार इन दुर्घटनों के लिये रेल चालकों या गार्डों, सिग्नलिंग विभाग या दूसरे अन्य कर्मचारियों को दोषी ठहराकर पल्ला झाड़ लेता है।

जबकि इन दुर्घटनाओं के होने की मूल समस्याओं के प्रमुख कारण हैं – भारतीय रेल में लगभग 3,12,000 पदों का खाली होना, सिग्नलिंग सिस्टम की खामियां, पटरियों के रखरखाव में कमी। ध्यान रहे कि पटरियों का रखरखाव करने वालों के काम की स्थितियां इतनी असुरक्षित होती हैं कि आये दिन 2–3 लोग काम करते समय मर जाते हैं! और ठेके पर नियुक्त किये गये अप्रशिक्षित मज़दूरों को ऐसे कामों में लगाया जाता है, जिसके लिये नियमित मज़दूरों को महीनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके साथ–साथ आउट सोर्सिंग के ज़रिये ख़रीदे गये ख़राब पुर्जे भी एक कारण हैं।

वक्ताओं ने बताया कि आधिकारिक तौर पर प्रतिदिन 9 घंटे काम करना होता है। लेकिन, बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों के कारण, उन्हें दिन में 14–16 घंटे भी बिना आराम किये काम करना पड़ता है। रेल चालकों को लगातार रात की ड्यूटी करनी पड़ती है। अक्सर छुट्टी नहीं मिलती है और यहां तक कि पर्याप्त साप्ताहिक आराम भी नहीं दिया जाता है।

प्रतिदिन 9 घंटे की समय सीमा के साथ–साथ, अधिवेशन में रेल चालकों की प्रमुख मांगों को उठाया गया, जिन पर आगे संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया गया। इनमें शामिल हैं – पुरानी पेंशन योजना की बहाली; अगली ड्यूटी शुरू होने से पहले मुख्यालय एवं आउट स्टेशन पर पर्याप्त विश्राम; शंटिंग सुपरवाइज़र के बिना कोई भी शंटिंग कार्य रोकना; असिस्टेंट लोको पायलट (ए.एल.पी.) को रिस्क एलाउंस; मंडल की सभी लॉबियों में मूलभूत सुविधायें, शुद्ध पानी एवं स्वच्छ टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध हो; और महिला रनिंग स्टाफ के लिए महिला टॉयलेट उपलब्ध कराया जाए, आदि।

दूसरे सत्र में ए.आई.एल.आर.एस. के सदस्यों और पदाधिकरियों ने अपनी संगठनात्मक समस्याओं और उपलब्धियों पर विचार–विमर्श किया। गहन चर्चा और सलाह–मशवरा करने के बाद, शाम 4 बजे मुरादाबाद डिविज़न की नई कमेटी का गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। बहुत ही जोशपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में अधिवेशन का समापन हुआ।

http://hindi.cgpi.org/24099

काम की बिगड़ती स्थितियों के ख़िलाफ़ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का संघर्ष

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन (डब्ल्यू.बी.एम.एस.आर.यू.) का 19वां राज्य सम्मेलन हाल ही में 8 से 10 सितंबर 2023 के बीच सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया था। पश्चिम बंगाल में डब्ल्यू.बी.एम.एस.आर.यू. मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स (एम.आर.) की सबसे बड़ी यूनियन है और इसके लगभग 22,000 सदस्य हैं। इस क्षेत्र में मज़दूरों की बिगड़ती कामकाजी स्थितियों पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई।

देशभर में लगभग पांच लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स (एम.आर.) हैं और वे विभिन्न राज्यों में विभिन्न यूनियनों में संगठित हैं। ये यूनियनें राष्ट्रीय स्तर पर अपने फेडरेशन, एफ.एम.आर.ए.आई. के तहत एक साथ आई हैं।

फार्मास्युटिकल (दवा) कंपनियां एम.आर. के माध्यम से अपनी दवाओं का प्रचार करती हैं। इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को उन दवाओं के सैंपल पैकेट दिए जाते हैं जिन्हें कोई कंपनी प्रमोट करना चाहती है। एम.आर. विभिन्न क्लीनिकों और अस्पतालों में जाते हैं और इन दवाओं के मुफ़्त नमूने देते हैं। डॉक्टरों को इन विशेष ब्रांड की दवाओं को लिखने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है, न कि जेनेरिक दवाओं या अन्य दवा कंपनियों के ब्रांडों की दवाओं को लिखने के लिए। ज्यादातर मामलों में एम.आर. का वेतन उस दवा की बिक्री पर आधारित होता है। एम.आर. पर न्यूनतम वेतन क़ानून लागू नहीं होता है। स्थानीय दवा कंपनियों में एम.आर. को प्रति महीने लगभग 8,000–10,000 रुपये मिलते हैं, जबकि कुछ बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों में एम.आर. का वेतन अधिक हो सकता है।

इनके काम की बिगड़ती स्थितियों के दो मुख्य कारण हैं – एम.आर. के काम को विनियमित करने वाले क़ानून को रद्द करना और दवा कंपनियों द्वारा इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाना। 1976 का बिक्री संवर्धन अधिनियम, 2021 में संसद द्वारा चार श्रम संहिताओं के पारित हो जाने के बाद निरस्त किए गए 29 श्रम कानूनों में से एक था। दवा कंपनियों ने एम.आर. के कार्यभार और काम के घंटों को बढ़ाने के लिए इस क़ानून के निरस्त होने का फ़ायदा उठाया है। कंपनियां एम.आर. को ऐसी गतिविधियों को संचालित करने के लिए भी मजबूर कर रही हैं जो बिक्री संवर्धन गतिविधि के दायरे में नहीं आती हैं। ऐसी गतिविधि का एक उदाहरण है रक्त के नमूने और अन्य स्वास्थ्य जांचों के लिए शिविरों का संचालन करना, जिसके लिए एम.आर. के पास कोई प्रशिक्षण नहीं है।

बड़ी दवा कंपनियां भी एम.आर. की आवश्यकता को ख़त्म करती जा रही हैं और अपने प्रचार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रही हैं। कई बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां एम.आर. को दूरदराज़ के इलाकों में ट्रांस्फर कर रही हैं, उनका वेतन रोक रही हैं। कुछ मामलों में तो कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है।

अब दवा कंपनियां एम.आर. की निगरानी करने और उन्हें डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही हैं। पूरा वेतन पाने के लिए बिक्री लक्ष्य पूरा करने के लिये पूर्व शर्त बनाई जा रही है।

अपने कामकाज की बिगड़ती परिस्थितियों के ख़िलाफ़ लड़ने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एम.आर. दृढ़ संकल्प हैं। डब्ल्यू.बी.एम.एस.आर.यू. के सम्मेलन से पहले, 26 अगस्त को फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ.एम.आर.ए.आई.) ने "रोज़गार संबंधों में बदलाव की चुनौतियां" विषय पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक की। इस बैठक में सभी एम.आर. यूनियनों के बीच स्थिति की सामान्य समझ विकसित करने और नियोक्ताओं द्वारा नए काम और कार्यभार को थोपने से निपटने के लिए उचित तंत्र विकसित करने में मदद करने के लक्ष्य से एक पेपर जारी किया गया था। इसके बाद, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तर–पूर्वी राज्यों, ओड़िशा और बिहार में राज्य इकाइयों और उप–इकाइयों की बैठकें हुईं।

http://hindi.cgpi.org/24077

क्यूबा के समर्थन में ...

पृष्ठ 3 का शेष

रहे विरोध के बावजूद, अमरीका ने क्यूबा के ख़िलाफ़ अपनी नाकेबंदी और प्रतिबंध जारी रखे हैं, जो स्पष्ट रूप से "लोकतंत्र" और "मानवाधिकार" और "नियम–आधारित शासन" के रक्षक होने का दावा करने के उसके ढोंग का पर्दाफ़ाश करता है।

क्यूबा के लोगों को अपनी पसंद की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था अपनाने का पूरा अधिकार है। जिससे किसी दूसरे देश के लोगों को कोई नुक़सान नहीं पहुंचता है। क्यूबा ने अन्य देशों के ख़िलाफ़ अमरीकी साम्राज्यवाद की हमलावर गतिविधियों का निडरतापूर्वक विरोध किया है।

गौरवशाली और बहादुर क्यूबाई लोगों के ख़िलाफ़ अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा की गई अन्यायपूर्ण नाकाबंदी, प्रतिबंध और अन्य शत्रुतापूर्ण क़दमों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/24046

नौसेना के ठेका मज़दूरों की समस्यायें

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

नौसेना के दक्षिणी कमान के तहत भारतीय नौसेना की केरल के कोच्ची और कन्नूर में स्थित दो छावनियों में देश के अलग–अलग इलाकों से विभिन्न ठेकेदारों के ज़रिये हजारों ठेका मज़दूर काम कर रहे हैं। जिन्हें दोनों नौसैनिक छावनियों में हाउसकीपिंग, सफाई व अन्य सेवाएं देने के लिए भर्ती किया जाता है। उनमें से कई तो बीस साल तक काम करने के बाद भी ठेका मज़दूर ही बने हुये हैं!

दक्षिणी नौसेना कमान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने 10 सितंबर को आयोजित अपने राज्य स्तरीय सम्मेलन में इन मज़दूरों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी समस्याओं को श्रम उपायुक्त (केंद्रीय) के समक्ष बार–बार उठाया है।

इन ठेका मज़दूरों को क़ानूनी तौर पर मिलने वाले न्यूनतम वेतन से वंचित किया जाता है। उनके पास न तो नौकरी की सुरक्षा है और न ही सामाजिक सुरक्षा के कोई उपाय हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, वे 617 रुपये प्रति दिन की मज़दूरी के पात्र हैं, जिसे हर छह महीने में संशोधित किया जाना चाहिए। हालांकि, कई ठेकेदार कंपनियों द्वारा नियुक्त मज़दूरों ने शिकायत की है कि उन्हें सरकार द्वारा घोषित वेतन नहीं दिया जा रहा है।

न ही ठेकेदारों द्वारा मज़दूरों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि (पी.एफ.) को मज़दूरों के खातों में जमा किया जा रहा है। मज़दूरों के मुताबिक ठेकेदार मज़दूरों के वेतन से 12 फ़ीसदी राशि रुपये काट लेते हैं। ठेकेदार उनके पी.एफ. खातों में 13 फ़ीसदी का योगदान करने के बजाय मज़दूरों के खातों में किसी भी राशि का भुगतान करते ही नहीं हैं। इससे मज़दूरों की मासिक आय में 25 प्रतिशत का नुक़सान हो जाता है।

मज़दूर विशेष रूप से इस तथ्य से परेशान हैं कि उनके प्रमुख नियोक्ता, यानी कि भारतीय नौसेना ने मज़दूरों की चिंताओं को दूर करने और आधिकारिक तौर पर निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के लिए ठेकेदारों को दंडित करने से लगातार इनकार किया है। अधिकांश ठेकेदारों की कंपनियों के पास पंजीकृत स्थानीय कार्यालय नहीं हैं और वे केंद्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में, ठेकेदारों और मज़दूरों को एक–दूसरे से मिलने का मौका तक नहीं मिलता है। मज़दूर अपनी समस्या ठेकेदार के सामने नहीं रख पा रहे हैं। ठेकेदार मज़दूरों को उचित मुआवज़ा दिए बिना ही अनुबंध को समाप्त कर देते हैं। मज़दूरों के विवादों और दावों के निपटारे के लिए यूनियन को ठेकेदार, प्रमुख नियोक्ता (यानी भारतीय नौसेना) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से संपर्क करने के लिये कठिन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ठेकेदार और प्रमुख नियोक्ता समझौते के लिए बार–बार उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे मज़दूरों की बकाया राशि मिलने में बाधा आती है।

आंदोलित मज़दूरों ने भारतीय नौसेना से अनुरोध किया है कि यदि ठेकेदार समय पर मज़दूरी का भुगतान नहीं करता है, तो अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम, धारा 21 (4) के अनुसार, भारतीय नौसेना मज़दूरों का भुगतान करे। उन्होंने गुजारा भत्ता, बोनस अधिनियम लागू करने की अपनी मांग को लेकर संघर्ष तेज़ करने का संकल्प लिया है और वे नौसेना से आग्रह कर रहे हैं कि वह ठेकेदार कंपनियों पर मुकदमा चलाये।

http://hindi.cgpi.org/24080

टमाटर की फ़सल पर एम.एस.पी. न होने का परिणाम :

किसानों को अपनी फ़सल को नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा

यह एक विडंबना ही है कि जब उत्पादकों को अपनी फ़सल नष्ट करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें अपनी फ़सल की लागत को हासिल करने के लिए क़ीमतें नहीं मिल पाती हैं। आज महाराष्ट्र के टमाटर उत्पादकों को इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

पिंपलगांव, नासिक और लासलगांव के थोक बाज़ारों में टमाटर की क़ीमतें जुलाई में 2,000–3,200 रुपये प्रति क्रेट (20 किलोग्राम) से गिरकर सितंबर में 90 रुपये प्रति क्रेट हो गई हैं। राज्य के कई जिलों में थोक क़ीमतों में इतनी भारी गिरावट के कारण टमाटर की खेती करने वाले लाखों किसानों के पास अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाने या अपने बागानों को छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है।

किसानों के मुताबिक, टमाटर की खेती करने के लिए एक किसान को पौधे, खाद और मज़दूरी पर प्रति एकड़ कम से कम एक लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। फ़सल को निकटतम मंडी तक ले जाने के लिए उसे 10,000 रुपये से 12,000 रुपये और खर्च करने पड़ते हैं। सितंबर के महीने में महाराष्ट्र के किसी भी थोक बाज़ार में उन्हें अपनी उपज की क़ीमत 70,000 से 80,000 रुपये से अधिक नहीं मिल पा रही थी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसानों ने फ़सल को बाज़ार तक ले जाने और मंडी में आगे का खर्च उठाने के बजाय अपनी उपज को खुद ही नष्ट कर दिया।

बताया जा रहा है कि टमाटर के लिए एम.एस.पी. तय करने की मांग को लेकर राज्यभर के किसानों के एक समूह ने सितंबर के आख़िरी सप्ताह में मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। सभी फ़सलों के लिये एम.एस.पी. की मांग लंबे समय से चली आ रही मांग है, जिसे नज़र–अंदाज़ कर दिया गया है। एक के बाद एक सरकारों के कृषि मंत्रालय ने सब्ज़ियों और फलों के लिए कोल्ड स्टोरेज के बारे में अनाप–शनाप बातें की हैं। ऐसा क्यों है कि टमाटर की खेती करने वाले किसानों को इतना आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराया गया है?

यह देश के लाखों किसानों की आजीविका और भलाई की आपराधिक उपेक्षा के अलावा और कुछ नहीं है। मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था कृषि व्यवसाय, बड़े थोक व्यापारियों और व्यापारिक कंपनियों और कृषि के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा

अन्य लागत वस्तुएं बनाने वाले पूंजीपतियों के हितों की सेवा करती है। कृषि नीति उनके मुनाफ़े को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जबकि मेहनतकश किसान और खेतिहर मज़दूर अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए लड़ रहे हैं। उनके श्रम की उपज बेतहाशा नष्ट हो रही है, जबकि लाखों मेहनतकश लोगों को महंगाई के कारण अपने भोजन में कटौती करनी पड़ती है।

http://hindi.cgpi.org/24083

बंगाल में परिवहन मज़दूर अपनी मांगों पर एकजुट

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

हिन्दोस्तानी राज्य मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता पर लगातार हमले कर रहा है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण करने तथा निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों को ठेके पर करवाने के क़दम उठा रहा है। केंद्र व राज्य सरकारें पूंजीपति मालिकों को मज़दूरों का शोषण बढ़ाने की खुली छूट देने के लिए मज़दूर–विरोधी क़ानून पारित कर रही हैं।

महंगाई और ज़रूरी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण मज़दूरों का जीवन स्तर गिर रहा है। बढ़ती बेरोज़गारी मज़दूरों को कम से कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि किसी भी नौकरी के लिए बेरोज़गारों की एक फ़ौज बेताब खड़ी है।

हिन्दोस्तान के अन्य हिस्सों के मज़दूरों की तरह, पश्चिम बंगाल में परिवहन मज़दूर भी अपने अधिकारों और सामान्य रूप से मज़दूरों के अधिकारों पर हो रहे इन हमलों का विरोध कर रहे हैं। वे ऐसे हमलों के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को तेज़ करने के लिए अटल हैं। इसी सिलसिले में वे मांगों का एक चार्टर लेकर आए हैं, जिसके इर्द–गिर्द वे एकजुट हो रहे हैं। जिसमें उनकी मुख्य मांगें हैं :

- केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण पर रोक;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाना और कमोडिटी बाज़ार में सट्टेबाज़ी पर रोक लगाकर मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए तत्काल उपाय;
- रोज़गार सृजन के ठोस उपायों के माध्यम से बेरोज़गारी पर काबू पाना;
- सभी बुनियादी श्रम क़ानूनों को कड़ाई से लागू करना और श्रम क़ानूनों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक उपाय;
- स्थायी काम में ठेका प्रथा को रोकना और समान काम के लिए ठेका मज़दूरों को नियमित मज़दूरों के बराबर वेतन;
- आवेदन करने की तारीख़ से 45 दिनों के भीतर ट्रेड यूनियनों का अनिवार्य पंजीकरण;
- रेलवे, बीमा और रक्षा में एफ.डी.आई. पर रोक।

http://hindi.cgpi.org/24073

जे.एन.यू. में ठेका मज़दूरों ने "सम्मान रैली" निकाली

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) के ठेका मज़दूरों के अधिकारों का क्रूरता से उल्लंघन हो रहा है। जैसे कि वेतन भुगतान में देरी, जाति के आधार भेदभाव सहित विभिन्न प्रकार के भेदभाव और नौकरी से निकाले जाने का लगातार ख़तरा।

18 सितंबर को इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए जे.एन.यू. में ठेका मज़दूरों ने "सम्मान रैली" आयोजित की। मज़दूरों ने समय पर वेतन न मिलने की समस्या उठाई, जिस कारण उनके परिवारों के दैनिक ख़र्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। सफ़ाई मज़दूरों ने ठेकेदारों और जे.एन.यू. अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। उन्होंने सुरक्षात्मक सामग्री उपलब्ध न कराये जाने की बात उठाई। सफ़ाई मज़दूरों के लिए सुरक्षात्मक सामग्रियों के न होने के कारण उनके स्वास्थ्य के लिये जोख़िम पैदा हो गया है। मज़दूरों ने कहा कि हमने कई बार मौखिक और लिखित शिक़ायतें दी हैं, लेकिन विभाग ने इस मुद्दे को हल नहीं किया है।

मज़दूरों ने बताया कि उन्हें बेहद कम वेतन मिलता है। मज़दूरों को आम तौर पर, मैस में 20 साल काम करने बाद, आज भी केवल 15,000 रुपये ही वेतन मिल रहा है।

आंदोलन को अगुवाई देने वाले मज़दूरों को नौकरी से निकाले जाने का डर बना रहता है। उनका कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलता है और समान काम के लिए समान वेतन भी नहीं दिया जाता है। इन अधिकारों की मांग करने पर हमारे ऊपर नौकरी से निकाले जाने का ख़तरा रहता है। यदि किसी मज़दूर की नौकरी छूट जाती है तो बाद में उसे ठेकेदार को उसी तरह की नौकरी, उतने ही वेतन और उसी प्रकार की असुरक्षित नौकरी पाने के लिए 40,000–50,000 रुपये देने पड़ते हैं।

सन 2000 से केंद्र सरकार के इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने मज़दूरों

शेष पृष्ठ 7 पर

कनाडा में सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूरों का प्रदर्शन

23 सितंबर, 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के 1,00,000 से अधिक मज़दूरों ने अपने अधिकारों की मांग के लिए मॉन्ट्रियल में जुलूस निकाला। उनके साथ बच्चों की देखभाल करने वाले केंद्रों के कर्मी, शिक्षक, छात्र और अन्य लोग शामिल हुए। वे क्यूबेक प्रांत के कोने–कोने से सरकार को यह दिखाने आए थे कि वे सरकार के आदेशों और उसके द्वारा थोपी गई काम और आवास की भयानक स्थितियों को नहीं मानते हैं। जुलूस में "हम एक आवाज़ के साथ!" नारे के साथ बैनर, झंडे, टोपियां और स्कार्फ लहरा रहे थे। यह नारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी मज़दूरों की उनकी मांगों को लेकर एकजुटता को

दर्शाता है कि काम की स्थितियां सामाजिक ज़िम्मेदारियों के अनुरूप होनी चाहिये।

प्रदर्शन पेलेस डेस फेस्टिवल्स पर समाप्त हुआ, जहां सभी वक्ताओं ने इस बात की पुष्टि की कि सार्वजनिक सेवा के लाखों मज़दूर पूरी आबादी को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि क्यूबेक के अधिकांश लोग उनके संघर्ष का समर्थन करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार मज़दूरों की मांगों पर बातचीत करने से इनकार कर रही है। इसलिए वह ही इन सेवाओं में आ रही बाधाओं के लिए ज़िम्मेदार है।

http://hindi.cgpi.org/24065

अमरीका की कार कंपनियों के मज़दूरों की हड़ताल

अमरीका में कार कंपनी के मज़दूर वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। फोर्ड मोटर कंपनी में 15 अगस्त, 2023 को हड़ताल शुरू हुई थी। 22 अगस्त तक अन्य दो बड़ी कार कंपनियों, जनरल मोटर्स (जी.एम.) और स्टेलेंटिस (जो अमरीका की फिएट क्रिसलर कंपनी और यूरोपीय पी.एस.ए. समूह के विलय से बनी थी) के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल का नेतृत्व यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स (यू.ए.डब्ल्यू.) कर रहा है – जो तीनों प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के मज़दूरों का यूनियन है। बताया जा रहा है कि जी. एम. और स्टेलेंटिस कंपनियों की कारों के पुर्ज़ों का वितरण केंद्र, जो उनकी मरम्मत सुविधाओं के लिए पुर्ज़ों की आपूर्ति करते हैं, उनके मज़दूर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं।

हालांकि ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने मज़दूरों के साथ अलग–अलग बातचीत कर रही हैं और "द बिग थ्री" वाहन निर्माता कंपनियों से बेहतर वेतन के प्रस्तावों के संदर्भ में कुछ प्रगति की सूचना मिली है, लेकिन मज़दूर 40 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की अपनी मांग पर डटे हुये हैं।

अमरीका में कार कंपनियों के मज़दूरों का कहना है कि 2003 के बाद से, हमारे वेतनों में औसतन प्रति घंटा 30 प्रतिशत की गिरावट हुई है। इस बीच, पिछले एक दशक में, "द बिग थ्री" वाहन निर्माताओं ने 250 अरब डॉलर से अधिक का मुनाफ़ा कमाया है और शेयर धारकों को स्टॉक बायबैक और लाभांश भुगतान में दसियों अरब डॉलर का लाभ दिया है।

मज़दूरों द्वारा दिया जा रहा तर्क उचित हैं कि जब शीर्ष प्रबंधन को मुनाफ़े में से भरपूर पारितोषिक दिया जा रहा है, तो मज़दूरों का वेतन कम से कम जीवनयापन के बढ़ते खर्च के अनुरूप तो होना ही चाहिए। उदाहरण के लिए, जनरल मोटर्स के सी.ई.ओ. ने 2022 में 29 मिलियन डॉलर कमाए, जो कंपनी के मज़दूरों के औसत वेतन का 362 गुना है। स्टेलेंटिस के सी.ई.ओ. ने 24.8 मिलियन डॉलर या औसत मज़दूर के वेतन से 365 गुना कमाया। फोर्ड के सी.ई.ओ. ने 21 मिलियन डॉलर कमाए, जो मज़दूर की औसत कमाई से कम से कम 281 गुना है।

फोर्ड और जनरल मोटर्स ने चार साल के अनुबंध के दौरान वेतन में 20 प्रतिशत और स्टेलेंटिस ने 21 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। यह बढ़ते कॉर्पोरेट मुनाफ़े और प्रबंधन को मिलने वाले बढ़ते भत्तों की पृष्ठभूमि में, ऑटो मज़दूरों के साल दर साल कम होते वेतन की भरपाई के लिए यू.ए.डब्ल्यू. द्वारा की जा रही 40 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की मांग काफ़ी कम है।

मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था दुनियाभर में करोड़ों लोगों की संपत्ति को एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में संकेंद्रित कर रही है। 1970 में, अमरीका में एक सीईओ की औसत आय एक मध्यम स्तर के मज़दूर की आय से 20 गुना थी। 1989 तक यह अनुपात बढ़कर 59 गुना हो गया और अब यह 300 गुना से भी अधिक हो गया है। 1970 में अमीर व्यक्तियों पर 70 प्रतिशत आयकर लगता था, जबकि अब सिर्फ़ 37 प्रतिशत है। अमरीका की फेडरल सरकार 1970 में कंपनियों से अपने करों का 12 प्रतिशत एकत्र करती थी, अब वह केवल छह प्रतिशत एकत्र करती है। इस प्रकार अमरीकी सरकार मज़दूरों के शोषण की मात्रा को लगातार बढ़ा रही है।

http://hindi.cgpi.org/24069

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के मज़दूरों का संघर्ष

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.ई.सी.) के मज़दूरों ने 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि 18 महीनों से रुके हुये वेतन का तुरंत भुगतान किया जाये। वे सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण पीएसयू की जानबूझ कर की जा रही उपेक्षा, कंपनी को बंद करने की सरकार की योजना के ख़िलाफ़ हैं। वे मांग कर रहे हैं कि इस पीएसयू का तत्काल आवश्यक आधुनिकीकरण हो।

रांची में स्थित एच.ई.सी. के संयंत्र लगभग 5,000 एकड़ भूमि पर फैले हैं। झारखंड के 'अनमोल गहने' के रूप में लोकप्रिय, एच.ई. सी. ने कई महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं में सेवाएं दी हैं। एच.ई.सी. ने चंद्रयान–3 और आदित्य एल–1 जैसी परियोजनाओं के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को तकनीकी सेवाएं दीं। इसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम और दुर्गापुर में प्लांट बनाने में भी मदद की है। इसने हिन्दोस्तान के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन जैसे भारी हथियारों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की सहायता की है। विभिन्न उद्योगों में एच.ई.सी. निर्मित मशीनों का उपयोग किया जाता है। एच.ई.सी. निर्मित मशीनों का उपयोग कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और अन्य जगहों में कोयला निकालने के लिए किया जाता है।

एच.ई.सी. के कर्मचारियों ने बताया कि इतने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद सरकार इस कंपनी को जानबूझकर उपेक्षित कर रही है और गहरे वित्तीय संकट में डूबा रही है। इसके अधिकांश बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षमता के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने इसके लिए धन देने से मना कर दिया है।

2012–13 से कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ने लगी। दिसंबर 2018 में एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि एच.ई.सी. को लगातार घाटा हो रहा था और 1992 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इसे बीमार घोषित कर दिया था। बोर्ड ने 2004 में कंपनी को बंद करने की सिफ़ारिश की थी। एच.ई.सी. को बकाया और अन्य क़र्ज़ों के निपटान के लिए दो बार विशेष पैकेज प्रदान किया गया था। कंपनी ने अपनी 675.43 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को बेचकर 742.98 करोड़ रुपये जुटाये। 2006–07 में 2.86 करोड़ और 2013–14 में 299.31 करोड़ रुपये का लाभ भी कमाया।

प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के वादों के बावजूद, एच.ई.सी. का आधुनिकीकरण कभी शुरू ही नहीं किया गया। समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि भारी उद्योग मंत्रालय आधुनिकीकरण के साथ आगे नहीं बढ़ा; इसके बजाय, इसने केवल क़ाग़ज़ों पर योजनाओं का मसौदा तैयार किया। समिति ने एक तकनीकी मूल्यांकन किया था और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को समयबद्ध आधार पर आधुनिकीकरण – सह – पुनरुद्धार योजना लागू करने की सिफ़ारिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

सरकार द्वारा जानबूझकर की गई इसकी उपेक्षा के कारण एच.ई.सी. का वर्तमान संकट उत्पन्न हुआ है। अब लगभग 18 महीनों से अपने वेतन से वंचित, एच.ई.सी. के कई कर्मचारी दो वक़्त की रोटी के लिए चाय और अख़बार बेचने को मजबूर हैं।

कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने, अपने लंबित वेतन को तत्काल पाने और आधुनिकीकरण–सह–पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए दृढ़संकल्प हैं।

http://hindi.cgpi.org/24061

जे.एन.यू. के ठेका मज़दूर ...

पृष्ठ 6 का शेष

को ठेके पर रखना शुरू किया था। मैस, सफ़ाई, सुरक्षा और प्रशासन में अधिकांश कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं। उनको गंभीर शोषण, आजीविका की असुरक्षा तथा ख़तरनाक और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

प्रदर्शनकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि जे.एन.यू. प्रबंधन उन्हें स्थायी श्रमिकों के रूप में मान्यता दे और वैधानिक वेतन के साथ–साथ, उन्हें मिलने वाले अन्य सभी लाभ भी दे।

http://hindi.cgpi.org/24075

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Oct, 2023, Date of publish - 1 Oct, 2023

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर राजस्थान में कार्यक्रम

हनुमानगढ़ में विचार गोष्ठी

27 सितम्बर, 2023 को राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ की उप–तहसील रामगढ़ में भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी हुई। इसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय था – वर्तमान में भगतसिंह के विचारों की प्रासंगिकता। भगत सिंह मेमोरियल शिक्षण समिति की अगुवाई में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम का आरंभ में बहुत ही जोश के साथ नारे लगाए गए – 'इंक़लाब जिंदाबाद!', 'समाजवाद ज़िंदाबाद!', साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!

इस कार्यक्रम में गांव के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में नौजवान, बच्चे और महिलाएं उपस्थित थीं।

नौजवानों और बच्चों ने क्रांतिकारी गीतों पर नृत्य पेश किये। उन्होंने छोटे–छोटे वक्तव्यों और नाटकों के ज़रिये भगत सिंह के विचारों को पेश किया और उपस्थित लोगों से भगत सिंह के रास्ते पर चलने का आह्वान किया।

विचार गोष्ठी को संबोधित करने वालों में थे – हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी से कामरेड बिरजू नायक, मज़दूर एकता कमेटी से संतोष कुमार, राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) से राममूर्ति स्वामी, अशोक वर्मा, भूप साहू, ओम सांगर, मणिराम लकेशर, अजय बाल्मिकी, दिनेश, राजगुरू, इत्यादि।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की और से कामरेड बिरजू नायक ने शहीद भगत

सिंह की दूरदर्शी बातों को याद दिलाया। भगत सिंह ने कहा था कि "हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठीभर लोग अपने हित के लिए मेहनतकशों का शोषण करते रहेंगे। शोषणकर्ता चाहे हिन्दोस्तानी हो या अंग्रेज़ या दोनों का गठबंधन, कोई हमें इस रास्ते पर चलने से नहीं रोक सकता"। अंग्रेजों ने 1947 में राज्य सत्ता हिन्दोस्तान के पूंजीपतियों को सौंपी थी। पूंजीवादी हुक्मरानों ने अपने राज्य में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गयी शासन व्यवस्था व दमन के तंत्रों को बरकरार रखा तथा उन्हें और कुशल बनाया। इस राज्य तंत्र के सहारे मज़दूरों और किसानों का शोषण करके तथा कुदरती संसाधनों को लूटकर, अब वे विश्व स्तरीय इजारेदार पूंजीपति बन गए हैं। वे ही हिन्दोस्तान के असली हुक्मरान हैं। इस हुकूमत की जगह पर मज़दूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करके ही इस देश के तमाम मेहनतकशों का भविष्य खुशहाल हो सकता है। इसके लिए मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को लामबंध करना ही शहीद भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

कई अन्य वक्ताओं ने कहा कि हुक्मरानों ने भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को गुमराह करने के लिए किया है। उन्होंने भगत सिंह को मूर्ति के रूप में स्थापित करके उनके क्रांतिकारी विचारों की धार को कुंद करने का काम किया है। हमें नौजवानों और बच्चों को भगत सिंह के विचारों से लैस करना होगा। तभी हम पूंजीवाद को हरा सकते हैं और मज़दूरों–किसानों का राज स्थापित कर सकते हैं।

विचार गोष्ठी का समापन लोक राज संगठन के सर्वहिंद उपाध्यक्ष कामरेड हनुमान प्रसाद शर्मा के वक्तव्य से हुआ। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को यह समझाना होगा कि हिन्दोस्तान पर पूंजीपति वर्ग राज करता है। भगत सिंह जिन काले अंग्रेजों का जिक्र करते हैं, वे ही हमारे हुक्मरान हैं। इस बात को सभी लोगों को समझाना हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में क़रीब 150 इजारेदार पूंजीवादी घराने हुक्मरान पूंजीपति वर्ग की अगुवाई करते हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था की दिशा को निर्धारित करते हैं। वे देश की नीति को निर्धारित करते हैं। राज्य के सभी संस्थान उन्हीं के हितों की सेवा में काम करते हैं। यह राज्य मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी और जन–विरोधी है। पूंजीवाद बेरोज़गारी का जनक है। जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक सबको रोज़गार नहीं मिल सकता है। हमें लोगों को देश की बागडोर खुद अपने हाथों में लेने के लिए जागृत करना होगा।

भादरा में इंक़लाब रैली

27 सितंबर, 2023 को राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ की तहसील भादरा की अनाज मंडी में इंक़लाब रैली हुई। यह रैली शहीद भगत सिंह के 116वें जन्म दिवस के अवसर पर की गई थी। इस इंक़लाब रैली में भादरा और इसके आस–पास के गांवों से मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों ने हजारों की संख्या में हिस्सा लिया।

इसके बाद अनाज मंडी से लेकर शहीद भगत सिंह चौक तक जुलूस निकाला गया। जूलूस में महिलाओं की भागीदारी हजारों में थी। भादरा के विधायक कामरेड बलवान पुनिया ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया।

http://hindi.cgpi.org/24104

किसान अपने दावे पर डटे हैं

पृष्ठ 1 का शेष

इस बीच, हरियाणा के किसानों ने बाढ़, कम बारिश और कीटों के हमले के कारण फ़सल को हुए नुक़सान के मुआवज़े की मांग करते हुए हिसार से चंडीगढ़ तक पदयात्रा की।

एक किसान कार्यकर्ता ने कहा, "हिसार में चार महीने तक धरना देने के बाद हमें आंशिक सफलता मिली। अब, हम किसानों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। किसानों की मांगें पूरी होने तक हम चंडीगढ़ में "पक्का मोर्चा" शुरू करेंगे। किसान पगड़ी संभाल जट्टा (पी.एस.जे.) के बैनर तले लड़ रहे हैं।

किसानों ने कहा कि बीमा कंपनी 2021 और 2022 के लिए 700 करोड़ रुपये के दावे की भरपाई करने से इंकार कर रही थी। 26 मई को पी.एस.जे. द्वारा हिसार में धरना शुरू करने के बाद, सरकार ने हस्तक्षेप किया और बीमा कंपनी को लगभग 400 करोड़ रुपये के दावों के मुआवज़े जारी करने पड़े। 67 गांवों के किसानों के दावे अब भी लंबित हैं।

करनाल जिले में धान की ख़रीद की धीमी गति के विरोध में किसानों ने तरावड़ी और निगधू की अनाज मंडियों में ताला लगा दिया।

http://hindi.cgpi.org/24089

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का नया प्रकाशन

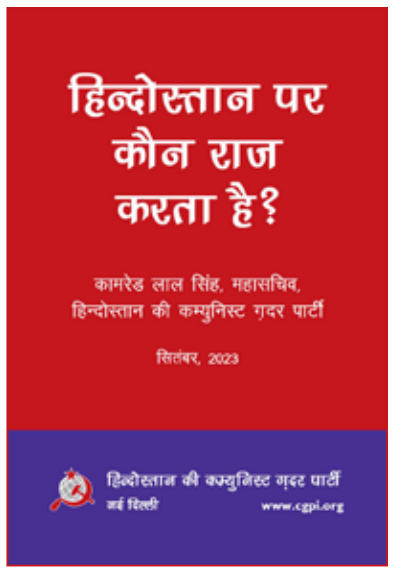

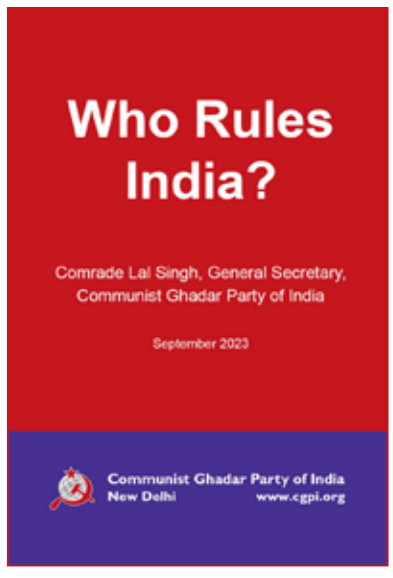

हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी एवं तमिल में उपलब्ध

मूल्य 50 रुपये (डाक खर्च के लिये 30 रुपये अलग से भेजें)

प्राप्त करने के लिये संपर्क करें :
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2,
नई दिल्ली – 110020,
फोन : 09810167911, वाट्सएप नम्बर 9868811998

UPI कोड से पेमेंट करें